VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1835)

Name of Candidate	Vikas Gupta		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	137029
Center	online	Date	5/9/22.

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट 'स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Be

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. The withdrawal of general consent to the CBI by certain state governments in India threatens the spirit of cooperative federalism in India. Discuss. **(150 words) 10**

भारत में कुछ राज्य सरकारों द्वारा सी. बी. आई. से सामान्य सहमति वापस लेना भारत में सहकारी संघवाद की भावना के लिए खतरा उत्पन्न करता है। चर्चा कीजिए।

हाल ही में पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों द्वारा CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली गयी। यह सहमति CBI को सुचारु रूप से राज्य के भीतर कार्य करने में मदद करती है।

प्रभाव

→ केस के संबंध में जांच के दौरान बार-बार राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता।

→ CBI द्वारा जांच में देरी।

सामान्य सहमति वापस लेना सहकारी संघवाद के खतरे के रूप में

→ इससे केंद्र व राज्यों के मध्य तनाव में वृद्धि होगी व सहयोग बाधित होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ राज्यों द्वारा CBI के कार्यों में हस्तक्षेप करने से एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में CBI के प्रभावी रूप से कार्य में रुकावट।

→ भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में CBI की प्रभावशीलता में कमी की संभावना।

यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सामान्य सहमति राज्य सरकारों का विशेषाधिकार है व संघीय भावना के अनुरूप है।

तथापि राज्यों को बिना ठोस कारण CBI को दीर्घ सामान्य सहमति वापस लेने से बचना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Stating the sources of finance for local self-governments in India, suggest ways to strengthen their financial position. (150 words) 10

भारत में स्थानीय स्व-शासी सरकारों के लिए वित्त के स्रोतों का उल्लेख करते हुए, उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उपाय सुझाइए।

भारत में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा एक प्रभावी स्थानीय स्वशासी ढांचे के निर्माण का प्रयत्न किया गया है।

वित्त के स्रोत

ग्रामीण पंचायत	नगरपालिका
* 11वीं अनुसूची के अंतर्गत विषय	* 12वीं अनुसूची के अंतर्गत विषय
↳ मेलों, हाटों का आयोजन द्वारा शुल्क संग्रहण, भवनों पर कर आदि	↳ भवनों पर कर, जलापूर्ति पर कर, जन्म-मरण सांख्यिकी निर्माण पर शुल्क आदि।
* राज्य द्वारा राज्य वित्त आयोग के सुझाव पर हस्तांतरण	* राज्य वित्त आयोग के सुझाव पर हस्तांतरण
* केंद्र द्वारा अनुदान	केंद्र द्वारा अनुदान।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

~~वित्तीय~~ इन स्रोतों के बावजूद स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं रही है। वर्तमान में शहरी स्वशासी ~~संस्था~~ संस्थाओं द्वारा कर संग्रहण GDP का मात्र 1% है, जबकि OECD देशों में यह ~~मात्र~~ 4% है।

वित्तीय स्थिति सुधारने उपाय

→ राज्यों द्वारा समय पर वित्त आयोग का गठन एवं सिफारिशों पर अमल करना।

→ राज्यों द्वारा विषयों का हस्तांतरण।

→ केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान व कर साझाकरण का एक निश्चित हिस्सा स्थानीय संस्थाओं के लिए आरक्षित करना।

स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारकर वास्तव में प्रत्यक्ष व विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की स्थापना में 73वें (विकेन्द्री,

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Cabinet Committees play an important role in reinstating collective responsibility and principle of homogeneity of the Executive in the Indian Parliamentary system. Elucidate. **(150 words) 10**

भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडलीय समितियां सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका की एकरूपता के सिद्धांत को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्पष्ट कीजिए।

मंत्रिमंडलीय समितियां कैबिनेट के मंत्रियों व अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती हैं। जैसे सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति। सामान्यतः इनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।

सामूहिक उत्तरदायित्व में भूमिका

भारत में अनु. 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

कैबिनेट समिति के माध्यम से छोटे समूह के माध्यम से निर्णय लेने में मदद मिलती है। ये समितियां समूचे मंत्रिपरिषद की ओर से निर्णय लेती हैं।

इस प्रकार संसद में जवाबदेही

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

तय करने में आसानी होती है। साथ ही विभिन्न विषयों पर इनकी बैठकें के माध्यम से संसद को सरकार की मंशा का पता चलता है।

कार्यपालिका के दक्षता के स्थिति में मदद

कैबिनेट समिति के माध्यम से आम निर्णय लेने में आसानी होती है। साथ ही एक समूह के रूप में इनके निर्णय को मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाता है। जो दक्षता में मदद करता है।

समस्या → सभी मंत्रियों की राय स्पष्ट नहीं हो पाती।

→ प्रधानमंत्री की तानाशाही की संभावना।

इन समस्याओं के बावजूद कैबिनेट समितियाँ प्रभावी व त्वरित निर्णय में मददगार होती हैं।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. There is a need to overhaul the public procurement and project management (PPPM) framework of India for faster, efficient and transparent execution of government projects. Comment.

(150 words) 10

सरकारी परियोजनाओं के तीव्र, कुशल और पारदर्शी निष्पादन के लिए भारत के सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन (PPPM) ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

भारत में विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए अवसंरचना निर्माण एवं कल्याणकारी राज्य के अनुरूप सरकारी परियोजनाओं का संचालन किया जाता है।

तथापि वर्तमान में ये परियोजनाएं देरी व भ्रष्टाचार से ग्रसित है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 400 परियोजनाओं में देरी के कारण सरकार को ₹4 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है।

भारत के सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता :-

1) परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी के लिए

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए।

→ विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कार्टेल का निर्माण कर सरकारी धन की हानि को रोकने।

→ परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं पारदर्शिता में वृद्धि हेतु।

उपाय

→ सार्वजनिक खरीद के लिए गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस का प्रयोग।

→ ठेके का आवंटन देने स्विस चैलेंज मॉडल का उपयोग।

→ परियोजनाओं में भुवन पोर्टल के माध्यम से जियोटैगिंग।

→ सरकारी विभागों द्वारा निजी कंपनियों के सत्यनिष्ठा समझौते।

→ परियोजनाओं की नियमित निगरानी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Adequate measures are required to overcome the challenges and vulnerabilities associated with undertaking social accountability initiatives and institutionalising them. Elaborate. (150 words) 10

सामाजिक जवाबदेही पहलों को शुरू करने और उन्हें संस्थागत बनाने से जुड़ी चुनौतियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए पर्याप्त उपायों की आवश्यकता है। सविस्तार वर्णन कीजिए।

सामाजिक जवाबदेही पहलें ऐसे प्रयास होते हैं जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं की प्रभाविता की जाँच व मूल्यांकन किया जाता है।

भारत में मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) आदि सामाजिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए निर्मित प्रयास हैं।

संबंधित चुनौतियाँ व कमजोरियाँ

→ नागरिकों में परियोजनाओं के मूल्यांकन की क्षमता की कमी।

→ नागरिकों में सामाजिक अंकेक्षण जैसे

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अधिकारों के संबंध में जागरूकता की कमी।

→ पंचायती संस्थाओं के प्रतिनिधियों की लोकसेवकों पर निर्भरता।

→ ग्राम सभा की नियमित बैठक नहीं।

→ प्रशासन में गोपनीयता की संस्कृति व भ्रष्टाचार।

उपाय

→ नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने नुक्कड़ नाटकों व NGO का सहयोग।

→ नागरिकों का क्षमता निर्माण व तकनीकी कौशल प्रदान करना।

→ सामाजिक जवाबदेही तंत्र में NGOs की भागीदारी बढ़ाना।

→ ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. In view of the recent Parliamentary Standing Committee report, discuss the issues faced by the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) and suggest measures that can be adopted to strengthen it. **(150 words) 10**

एक संसदीय स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों की विवेचना कीजिए और इसे मजबूत बनाने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 89वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के हितों का संवर्धन व उनका शोषण रोकना है।

हालांकि हाल ही में संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट में कहा कि NCST द्वारा पिछले 4 वर्षों से कोई रिपोर्ट जमा नहीं की गई है।

NCST द्वारा सामना किये जाने वाले मुद्दे :-

1) आयोग को अयोग्य राजनेताओं, लोगों को एक ठिकाना बना दिया गया है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ आयोग की रिपोर्ट पर संसद में नियमित चर्चा नहीं की जाती है।

→ आयोग द्वारा साक्ष्य आधार पर जनजातियों के द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता।

→ आयोग के पास प्रशिक्षित कर्मियों की कमी।

→ आयोग ~~द्वारा~~ एवं जनजातियों के मध्य कार्य करने वाले NGO के मध्य सहयोग की कमी।

उपाय

→ आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के चयन में पारदर्शिता लाना।

→ आयोग व जनजातियों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे NGOs के मध्य संपर्क में वृद्धि।

→ आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हेतु पृथक समय का आवंटन।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. While the Mid-Day Meal scheme was aimed at fulfilling the nutritional needs of students, it is far behind in achieving this objective. Discuss. Also, suggest remedial measures in this context. **(150 words) 10**

यद्यपि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य छात्रों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था, किंतु इस उद्देश्य को प्राप्त करने में यह काफी पीछे है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए।

मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 1995 में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के साथ उनकी पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।

विफलता

वर्तमान में भी भारत के लगभग एक तिहाई बच्चे स्टंटिंग व 50% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी भारत 116 देशों में 101 वें स्थान पर है।

कारक

→ प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण निम्न गुणवत्ता का भोजन।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ खाद्यान्न में विविधता की कमी होना।

→ कई बार वित्त के आवंटन में देरी के कारण खाद्यान्न प्राप्त न होना।

उपाय

→ फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा।

→ खाद्यान्न में विविधता जैसे मोटे अनाज को बढ़ावा।

→ भ्रष्टाचार रोकने पारदर्शिता में वृद्धि करना।

→ सामाजिक अंकेक्षण करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Sexual and reproductive health and rights (SRHR) remain critical for the attainment of the Sustainable Development Goals (SDGs). In this context, discuss the impediments in the fulfilment of SRHR in India. Also, mention the steps that can be taken in this regard. **(150 words) 10**

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार (SRHR) महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में, भारत में SRHR की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार बच्चों के जन्म एवं नसबंदी संबंधी निर्णय लेने से संबंधित है,

SDG में योगदान

→ SDG-3 के अंतर्गत स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में।
→ SDG-5 के अंतर्गत लैंगिक समानता को बढ़ावा।

भारत में SRHR में बाधाएं

→ पितृसत्तावादी समाज।
→ महिलाओं के अधिकारों को मान्यता न दिया जाना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- महिलाओं में उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी।
- महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण न होने के कारण धन के लिए पुरुषों पर निर्भरता।

कदम

- जागरूकता अभियान का संचालन जिसमें आँगनवाड़ी व आशा कर्मियों की मदद।
- महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचनाओं का निर्माण।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. State the functions of the United Nations Human Rights Council. Also, discuss the issues faced by the Council in the promotion and protection of human rights around the globe. **(150 words) 10**

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्यों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, विश्व भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण में परिषद द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों की विवेचना कीजिए।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 2006 में किया गया।

कार्य

→ पूरे विश्व में मानवाधिकारों (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणापत्र में वर्णित) को बढ़ावा।

→ मानवाधिकारों पर चर्चा हेतु राष्ट्रों को मंच उपलब्ध करवाना।

→ राष्ट्रों की मानवाधिकार रक्षा की क्षमताओं में वृद्धि हेतु सहयोग करना।

→ मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति में

जाँच करना व संयुक्त राष्ट्र को रिपोर्ट देना जैसे हाल ही में चीन में उइघर प्रांत संबंधी रिपोर्ट।

परिषद् द्वारा सामना किये जाने वाले मुद्दे

→ क्रियान्वयन के लिए सदस्य राष्ट्रों पर निर्भरता।

→ सुझाव राष्ट्रों पर बाध्यकारी नहीं।

→ पाकिस्तान जैसे मानवाधिकार उल्लंघनकारी राष्ट्र को परिषद् में सदस्यता मिलना।

→ राष्ट्रों द्वारा परिषद् की रिपोर्ट पर कार्यवाही न करना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. West Asia is an important strategic region for India with profound geo-political and geo-economic significance. Discuss. **(150 words) 10**
अत्यधिक भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक महत्व के कारण पश्चिम एशिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है। चर्चा कीजिए।

पश्चिम एशिया क्षेत्र ~~खाड़ी~~ फारस की खाड़ी में स्थित देशों व ईरान को समाहित करता है।

भू-राजनीतिक महत्व-

→ क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव

→ इस क्षेत्र में भारत के 8.5 मिलियन प्रवासी की उपस्थिति।

→ ईरान व सऊदी अरब के मध्य प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं।

→ एशिया में चरमपंथी व आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु।

भू आर्थिक महत्व- भारत अपने तेल

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आयात के दो-तिहाई भाग के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर।

→ भारत द्वारा निर्यात का महत्वपूर्ण बाजार जैसे यूएई भारत का इसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार।

→ पश्चिमी एशिया स्थित प्रवासियों द्वारा विप्रेषण।

→ सऊदी अरब व UAE द्वारा NEIP में निवेश द्वारा अवसंरचना निर्माण में मदद।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Disenfranchising prisoners desecrates a cherished value in a democracy i.e. 'right to vote', which should be guarded earnestly. Discuss in the light of The Representation of The People Act, 1951. **(250 words) 15**

कैदियों को मताधिकार से वंचित करना वस्तुतः लोकतंत्र के एक प्रशंसनीय मूल्य, अर्थात् "मतदान के अधिकार" का अपमान करना है, जिसकी गंभीरतापूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के आलोक में चर्चा कीजिए।

भारत में अनु. 326 के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की परिकल्पना की गई है। तथापि लोक-प्रतिनिधित्व अधि. 1951 के द्वारा कैदियों को मताधिकार से वंचित किया गया है।

जबकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। जहाँ मतदान का अधिकार नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है।

कैदियों को मताधिकार दिये जाने के पक्ष में तर्क

→ विचाराधीन कैदियों के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। इस स्थिति में विचाराधीन

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

कैदियों को मताधिकार से वंचित करना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता।

→ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पत्र में वोट देने के अधिकार को मूलभूत मानवाधिकार माना गया है।

इस स्थिति में कैदियों को मताधिकार से वंचित करना उनके मानवाधिकार का उल्लंघन है।

→ मतदान का अधिकार लोकतंत्र का मूल माना जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. There are similarities and interactions between the affirmative action adopted by India and USA owing to similar historical injustices faced by their respective vulnerable groups. Discuss. **(250 words) 15**

भारत और यू. एस. ए. के सुभेद्य समूहों द्वारा सामना किए गए एकसमान ऐतिहासिक अन्याय के कारण, इनके द्वारा अपनाई गई सकारात्मक कार्रवाई के बीच समानताएं हैं और इनका एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ा है। चर्चा कीजिए।

भारत और अमेरिका दोनों ही विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों में से एक हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने सुभेद्य वर्गों के उत्थान हेतु प्रयत्न किये हैं जैसे अमेरिका द्वारा अश्वेत वर्गों के उत्थान हेतु एवं भारत द्वारा दलित, पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु।

भारत व अमेरिका के मध्य सकारात्मक कार्रवाई में समानताएँ :-

→ दोनों ही देशों द्वारा 'विधि के समान संरक्षण' की अवधारणा को स्वीकार किया गया। ये दोनों देशों की सकारात्मक कार्रवाई का आधार।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ आरक्षण – अमेरिका में शिक्षण के क्षेत्र में अश्वेत समूहों को आरक्षण द्वारा प्राथमिकता दी गई। इसी प्रकार भारत में अनु. 15(4) द्वारा एवं अनु. 15(5) द्वारा शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण।

→ सामाजिक सुरक्षा योजनाएं- सुभेद्य वर्गों को आगे बढ़ाने व उनकी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति जैसे स्वास्थ्य सुनिश्चित करने दोनों देशों द्वारा प्रयत्न किया किये गये। उदा. अमेरिका में ओबामाकेयर व भारत में आयुष्मान भारत योजना।

अंतर

→ भारत में जहाँ नौकरियों में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई, वहीं अमेरिका में नौकरियों में आरक्षण लागू नहीं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ भारत में विशेष सरकारी उद्यमों की स्थापना की गई जबकि अमेरिका में ~~उद्यो~~ औद्योगिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा।

→ भारत में विधायिका (लोकसभा व ~~राज्यसभा~~ विधानसभा) के स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था है। जबकि अमेरिका में विधायिका में आरक्षण नहीं।

~~इ~~ इस प्रकार भारत व अमेरिका की सकारात्मक कार्रवाई में कुछ विचलन अवश्य है। तथापि दोनों ही राष्ट्रों के प्रयासों से सुभेद्य वर्गों की स्थिति में सुधार हुआ है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Objections to domicile-based reservation in private sector jobs on the grounds of constitutional equality and freedom are misplaced. Critically discuss. (250 words) 15

संवैधानिक समानता और स्वतंत्रता के आधार पर निजी क्षेत्रक की नौकरियों में अधिवास आधारित आरक्षण पर आपत्ति अनुचित है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

हाल ही में हरियाणा व आंध्रप्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थानीय समुदाय को 75% आरक्षण चर्चित रहा।

कई आलोचकों के अनुसार यह आरक्षण अनु 19 के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता व एवं अनु. 14 एवं अनु. 16 का उल्लंघन है।

स्थानीय समुदाय को आरक्षण के पक्ष में तर्क :-

1) बढ़ती बेरोजगारी- कंपनियों द्वारा बाहरी श्रमिकों महत्व दिये जाने के कारण राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है, जैसे CMIE के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी बढ़कर 35% हो गई है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ अनु. 16 केवल सरकारी नौकरियों में स्थानीयता के आधार पर नौकरियों को प्रतिषेध करता है न कि निजी क्षेत्र में।

→ राज्य के संसाधनों का उपयोग करने वाली कंपनियों की राज्य के नागरिकों के प्रति दायित्व की पूर्ति।

→ राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि में मदद।

→ राज्य के नागरिकों की आय में वृद्धि से नागरिकों के व्यय में वृद्धि व आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा।

विपक्ष में तर्क

→ यह भारत की एकल नागरिकता की संकल्पना के विरुद्ध।

→ इससे क्षेत्रवाद व भूमिपुत्र की संकल्पना को बढ़ावा मिलने की संभावना जैसे-

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

महाराष्ट्र मराठियों के लिए।

→ यह निजी क्षेत्र के लिए मानव संसाधनों के विकल्प को सीमित कर उनकी प्रतिस्पर्धा को कम कर सकता है।

→ निजी क्षेत्रों द्वारा निवेश हतोत्साहित हो सकता है।

→ ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है जो कंपनियों के सुचारू संचलन में बाधा उत्पन्न करेगा।

सुझाव

→ आरक्षण की बजाय राज्य में श्रम गहन कंपनियों को निवेश के लिए प्रेरित करना।

→ स्थानीय युवाओं में कौशल का विकास करना।

→ राज्य के नागरिकों में शिक्षा व स्वास्थ्य में सुधार कर मानव विकास को बढ़ावा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. There have been arguments that sedition law is an attack on the very foundation of India's liberal democratic principles, as enshrined in the Constitution. Do you agree? **(250 words) 15**
ऐसा तर्क दिया जाता है कि राजद्रोह कानून भारत के उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव पर हमला है, जैसा कि संविधान में निहित हैं। क्या आप सहमत हैं?

राजद्रोह कानून IPC की धारा 124-A में वर्णित है, जो विधि द्वारा स्थापित सरकार को अवैध रूप से हटाने के प्रयासों को विफल करने के लिए आजादी के बाद भी बनाये रखा गया।

आलोचना

राजद्रोह कानून अत्यंत कठोर कानून है जो चित्र, लिखित व मौखिक रूप से सरकार के विरुद्ध विचारों को प्रतिबंधित कर देता है। यह संविधान के निम्न मूल्यों के विरुद्ध है—

1) स्वतंत्रता - यह अनु 19 के अंतर्गत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिकूल है। कई बार राजद्रोह कानून

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

का उपयोग सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष की आलोचनाओं को दबाने के लिए उपयोग किया जाता है।

2) जीवन की स्वतंत्रता- राजद्रोह कानून वास्तव मे अनु. 21 की मूल भावना के विरुद्ध है।

3) लोकतंत्र में सरकार की आलोचना के द्वारा ही लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया जा सकता है, जबकि राजद्रोह की आड़ में सरकार सभी प्रकार की आलोचनाओं को दबाने का प्रयास करती है।

4) प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन।

5) तानाशाही सरकार का निर्माण।

हालांकि देश में विधि द्वारा स्थापित सरकार को अवैध तरीके

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

हटाने जैसे आतंकवादियों, चरमपंथियों के प्रयासों से बचाने कुछ उपाय आवश्यक हैं।

तथापि इसके लिए देश में UAPA, 1967 व भारतीय दंड संहिता के प्रावधान उपलब्ध है।

आगे की राह

विधि आयोग ने भी माना है कि या तो राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए या इसे हटा दिया जाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा राजद्रोह पर पुनर्विचार पूरा होने तक इसके क्रियान्वयन पर पूरे भारत में रोक लगा दी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Despite Government e-Marketplace facing certain challenges, it has brought about a significant improvement in the procurement of goods and services by various government agencies. Discuss. **(250 words) 15**

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस द्वारा कुछ चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, इन्होंने विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में महत्वपूर्ण सुधार किया है। चर्चा कीजिए।

सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा खरीद कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता में वृद्धि हेतु गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस का निर्माण किया गया था। यह एक इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ आपूर्तिकर्ता व सरकारी विभाग आपस में संपर्क स्थापित करते हैं।

चुनौतियाँ

- फेक वेंडर की उपस्थिति।
- गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति न होना।
- आपूर्तिकर्ताओं का सत्यापन न किया जाना।
- आपूर्तिकर्ताओं का समय पर भुगतान नहीं।

सकारात्मक प्रभाव

→ सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से पारदर्शिता में वृद्धि।

→ सभी आपूर्तिकर्ताओं को समान अवसर उपलब्ध होना।

→ आपूर्तिकर्ताओं के मध्य प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के कारण लागत में कमी।

→ सरकार के लिए उचित गुणवत्ता वाली वस्तुओं को खरीदने में आसानी

→ भ्रष्टाचार में कमी।

→ सरकारी विभागों को वस्तुएँ खरीदने विकल्पों में वृद्धि।

सुझाव

→ GEM में जुड़े वेंडर्स का सत्यापन करना।

→ निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएँ देने वाले वेंडर्स को बैन करना।

→ आपूर्तिकर्ताओं का समय पर भुगतान करना।

→ वेंडर्स की संख्या में वृद्धि का प्रयास करना।

इस प्रकार GEM का कुशल क्रियान्वयन सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार के साथ भारतीय प्रशासन में सुधार कर सकता है।

1835
VISION IAS™

16. A reformed system of recruitment, training and evaluation needs to be put in place to take forward the development of a highly efficient and accountable civil service. Discuss in the context of India. **(250 words) 15**

अत्यधिक कुशल और जवाबदेह सिविल सेवा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और मूल्यांकन की एक संशोधित प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

भारत में स्थायी कार्यपालिका के रूप में सिविल सेवा की परिकल्पना की गई है। जिसका मुख्य कार्य योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन करना है।

वर्तमान में समस्याएँ

→ कार्यकाल की सुरक्षा के कारण उदासीनता की प्रवृत्ति।

→ सिविल सेवकों में नवाचारी भावना की कमी।

→ परिणाम की जगह प्रक्रियाओं के पालन पर जोर।

→ पारदर्शिता की कमी एवं भ्रष्टाचार।

→ सिविल सेवकों में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता की कमी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस संदर्भ में निम्न रूप से संशोधित प्रणाली का निर्माण किया जा सकता है.

भर्ती के संदर्भ में

→ सामान्यज्ञों के साथ ही निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों की नियुक्ति।

→ प्रवेश परीक्षा में सुधार द्वारा वर्तमान में जटिल होते कार्यों के अनुरूप भर्ती।

↳ लेटरल एंट्री की सुविधा देना।

प्रशिक्षण के संबंध में

→ विभिन्न क्षेत्रों में रुचि के अनुरूप विशेषज्ञता निश्चित करने में मदद करना।

→ प्रशिक्षण के दौरान आम नागरिकों के साथ विभिन्न सरकारी विभागों एवं

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पंचायती राज संस्थाओं से संपर्क बढ़ाना।

→ डिजिटल कौशल का निर्माण करना।

→ प्रशिक्षण के मध्य में प्रशिक्षुओं को सर्विस बदलने का विकल्प देना।

→ प्रशिक्षण के दौरान व्यवहारिक कौशल निर्माण पर जोर देना।

मूल्यांकन के संदर्भ में

→ उच्चाधिकारियों के साथ ही मूल्यांकन में जनता की भी राय लेना। इसके लिए एक स्टार रेटिंग प्रणाली का निर्माण।

→ समकक्षों की राय जानना।

सरकार द्वारा प्रयास → लेटरल एंट्री द्वारा संयुक्त सचिवों की नियुक्ति

→ 360° मूल्यांकन व स्पैरो प्रणाली।

→ ~~प्रधानमंत्री~~ iGOT पोर्टल का निर्माण एवं मिशन कर्मयोगी।

17. Despite initiatives taken by the Indian government to achieve critical goals in the education sector, major interventions are required to tackle learning poverty as well as the persisting inequalities. Discuss. **(250 words) 15**

शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई पहलों के बावजूद, लर्निंग पॉवर्टी (अधिगम निर्धनता) के साथ-साथ विद्यमान असमानताओं से निपटने के लिए बड़े हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

~~सोर्निंग~~ वर्ल्ड बैंक के अनुसार लर्निंग पोवर्टी से तात्पर्य 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को सामान्य पाठ पढ़ने व समझने में कठिनाई से है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार कोविड-19 के कारण भारत में लर्निंग पोवर्टी की दर बढ़कर 70% हो गई है।

इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता के स्तर पर निरंतर असमानता में वृद्धि हुई है। जहाँ एक ओर निजी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर मजबूत हुआ है वहीं गरीब एवं वंचित वर्गों के लिए निर्मित सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता में गिरावट हुई है।

इस संदर्भ में निम्न प्रयास किए जाने की आवश्यकता है-

1) सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों की सुचारू ट्रेनिंग की व्यवस्था।

2) स्मार्ट क्लासरूम व नई तकनीकों जैसे AI व VR के माध्यम से ~~बच्चे~~ बच्चों के सीखने की क्षमता में वृद्धि करना।

3) डिजिटल शिक्षा के माध्यम से दूर-दराज के क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।

4) बच्चों की शैक्षणिक सामग्री की गुणवत्ता में सुधार करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5) छात्रों के द्वारा निरंतर फीडबैक लेकर शिक्षण व्यवस्था में सुधार को सतत प्रक्रिया बनाना।

इस प्रबंध में सरकार द्वारा कुछ नये प्रयास शुरू किये गये हैं—

1) स्वयंप्रभा चैनलों की शुरुआत।

2) निष्ठा पोर्टल द्वारा शिक्षकों की सहायता।

3) डिजिटल इंडिया मिशन एवं कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण।

4) नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माण।

वर्तमान में भारत ने शिक्षा में नामांकन में सुधार कर लिया है। अब प्रयास गुणवत्ता में सुधार के लिए किये जाने चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. In light of the burgeoning burden of both communicable and non-communicable diseases, there is a need to revamp the public health surveillance system in India. Discuss. **(250 words) 15**

संचारी और गैर-संचारी दोनों प्रकार के रोगों के बढ़ते बोझ के आलोक में, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

भारत वर्तमान में संचारी व गैर-संचारी दोनों प्रकार के रोगों का सामना कर रहा है। जहाँ एक ओर बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण व अपशिष्ट के कारण संचारी रोगों में वृद्धि हुई है। वहीं रहन सहन की आदतों में परिवर्तन के कारण गैर-संचारी रोगों जैसे डायबिटीज, हृदयाघात में वृद्धि हुई है।

इस संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता - संचारी रोगों के संबंध में

1) रोगजनकों की शुरुआत में पता चलने से वैक्सीन, दवा निर्माण में सहायता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2) रोगजनकों का विस्तृत अध्ययन द्वारा उनके म्यूटेशन की कार्यप्रणाली का अध्ययन एवं भविष्य के प्रकोप की भविष्यवाणी।

3) जीवाणुओं व विषाणुओं के संभावित स्रोतों का पता लगाने में।

4) उपचार की तकनीकों के निर्माण में मदद

गैर-संचारी रोगों के संबंध में

→ बढ़ते गैर संचारी रोगों के संबंध में उपचार हेतु शोध में मदद।

→ जनता के ~~नागरिकों~~ को गैर-संचारी रोगों से बचाव हेतु सुझाव देने में।

→ सरकारी नीतियों के निर्माण में।

इस संबंध में निम्न

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रयास किये जा सकते हैं:-

1) स्थानीय स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में रोगों के डेटा एकत्र करने हेतु प्रणाली का निर्माण।

2) देश में रोगाणुओं पर रिसर्च करने वाली लेबोरेटरीज की संख्या बढ़ाना।

3) आशा, ANM कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण।

4) देश के ~~अस्पतालों~~ अस्पतालों को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ना जिससे सरकार को स्थापित करने में सहायता मिले,

इस प्रकार नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार द्वारा SDG-3 की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. The repercussions of the ongoing economic crisis in Sri Lanka extend beyond its borders. Discuss with specific reference to India. Also, mention the steps that India has taken to assist Sri Lanka tide over the crisis.

(250 words) 15

श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट का प्रभाव उसकी सीमाओं से परे भी पड़ रहा है। भारत के विशिष्ट संदर्भ में विवेचना कीजिए। साथ ही, उन कदमों का भी उल्लेख कीजिए जो भारत ने इस संकट से निपटने में श्रीलंका की सहायता के लिए उठाए हैं।

हाल ही में श्रीलंका को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है एवं श्रीलंका सरकार द्वारा सोवरेन डेब्ट पर डिफाल्ट कर दिया गया है।

श्रीलंका में संकट का भारत पर प्रभाव

→ शरणार्थी- श्रीलंका में संकट के कारण तमिल शरणार्थियों का संकट बढ़ रहा है।

→ निकट के राज्य में एक फेल्ड स्टेट का निर्माण भारत के लिए चुनौतीभरा हो सकता है।

→ श्रीलंका भारत का तीसरा सबसे प्रमुख व्यापारिक भागीदार राष्ट्र है। इस लिहाज़ से

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

कारण श्रीलंका में संकट का भारत के निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

→ पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते भारत द्वारा श्रीलंका की मदद की जा रही है। किन्तु भारत स्वयं कोविड-19 आपदा के बाद से आर्थिक रिकवरी की ओर अग्रसर है। इसलिए भारत श्रीलंका की अधिक सहायता में असमर्थ है।

→ श्रीलंका की खराब आर्थिक स्थिति चीन के प्रभाव में वृद्धि कर सकती है।

→ आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका में चरमपंथी समूहों के उभरने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

भारत द्वारा श्रीलंका की सहायता

→ $4 बिलियन की आर्थिक सहायता।

→ श्रीलंका को गेहूं, चावल आदि खाद्यान्न की आपूर्ति।

→ श्रीलंका को ईंधन के रूप में पेट्रोलियम की आपूर्ति।

→ श्रीलंका में सुधार हेतु तकनीकी सहायता।

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा नेबरहुड फर्स्ट की नीति के तहत श्रीलंका की मदद का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. India is a reliable partner in the Indian Ocean Region and can take on the role of being the net security provider in the region. Discuss. **(250 words) 15**

भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार है और इस क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता होने की भूमिका निभा सकता है। विवेचना कीजिए।

हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। जहां से कुल वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 40% हिस्सा गुजरता है।

भारत की स्थिति हिंद महासागर क्षेत्र में केंद्रीय राष्ट्र की है, इस कारण भारत स्वयं को इस क्षेत्र में निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखता है।

भारत की निवल सुरक्षा प्रदाता की स्थिति के पीछे तर्क :-

→ हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य क्षमता की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली राष्ट्र।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ INS विक्रांत जैसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर वाला 6वाँ देश।

→ परमाणु पनडुब्बियों के मदद से लंबे समय तक नौसेनिक गतिविधियों को जारी रखने की क्षमता।

→ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हिंद महासागर में राजनीतिक अवस्थिति।

→ विश्व में 17वाँ सबसे बड़ा EEZ वाला राष्ट्र।

→ IONS व IORA जैसे मंचों में सक्रिय भागीदारी।

चुनौतियाँ

→ चीन द्वारा निरंतर हिंद महासागर क्षेत्र में गतिविधियों में वृद्धि जैसे हाल ही में श्रीलंका में चीनी पनडुब्बी की डॉकिंग।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ चीन द्वारा 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' की नीति के तहत रणनीतिक बंदरगाहों का निर्माण जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा का निर्माण।

→ अमेरिका द्वारा 'फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन्स' के माध्यम से भारतीय EEZ का उल्लंघन जैसा 2020 में हुआ।

→ भारतीय नेवी का विदेशी कंपनियों पर निर्भरता।

भारत द्वारा प्रयास

→ कोलंबो सिक्युरिटी डायलॉग का संचालन।

→ स्वदेशी विमानवाहक पोत (INS विक्रांत) का निर्माण।

→ सिंगापुर, जापान आदि से लॉजिस्टिक्स समझौते आदि।